P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-11* February- 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

विश्व राजनीति में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

International Monetary Fund in World Politics: An Analytical Study

राजेश कुमार टांक
शोधार्थी,
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
राजस्थान यूनिवर्सिटी,
जयपुर, राजस्थान भारत

सारांश

युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं व्यापारिक व्यवस्थाओं के प्रबंधन हेतु ब्रेटनवुड्स व्यवस्था की स्थापना की गई। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नियमन के लिए नियमों, संस्थाओं व प्रक्रियाओं की व्यवस्था का निर्धारण करने के साथ–साथ ब्रेटनवुड्स के योजनाकारों ने पुनःनिर्माण एवं विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना की। ब्रेटनवुड्स संस्थाओं की उत्पत्ति के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय परिदृष्य में निरन्तर अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना में अनेक राष्ट्र आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से शक्ति संपन्न उभरे है तो दूसरी ओर विश्व के विकसित एवं औद्योगिक रूप से सम्पन्न राष्ट्रों की शक्ति में ह्रास हुआ है। इसी सन्दर्भ में समकालीन अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका को समझना आवश्यक है।

The Bretton woods system was established to manage post-war international monetary and trade arrangements. Along with determining the system of rules, institutions and procedures for the regulation of the international political economy, the planners at Brettonwoods established the International Bank for Reconstruction and Development (PATH) and the International Monetary Fund (PD). After the birth of Brettonwoods institutions, many changes have been seen in the international scenario. In the international power structure, many nations have emerged economically and technically powerful, on the other hand, the power of developed and industrially rich nations of the world has erupted. It is in this context that it is necessary to understand the role of the International Monetary Fund in the contemporary international system.

मुख्य शब्द : राजनीति, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विनिमय दर।
Politics, International Monetary Fund, Exchange Rate.

प्रस्तावना

आईएमएफ के रूप में ब्रेटनवुड्स समझौते के रचनाकार जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्सटर व्हाइट ने एक ऐसी संस्था की कल्पना की थी जो अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, विनिमय दरों और अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों की देखरेख करेगी ताकि राष्ट्रों और उनके नागरिकों को एक–दूसरे से वस्तुएं और सेवाएं खरीदने में सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने आशा की थी कि यह नई वैश्विक इकाई विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करेगी और अपने सदस्य देशों को व्यापार में बाधा डालने वाले विनिमय प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आधिकारिक तौर पर, आईएमएफ दिसंबर 1945 में अठारह सदस्य देशों के साथ अस्तित्व में आया था। (ब्रेटन वुड्स में रहने वाले सोवियत संघ ने आईएमएफ में शामिल होने से इनकार कर दिया था) वर्ष 1947 में संस्थान के संचालन के पहले औपचारिक वर्ष में फ्रांस आईएमएफ से उधार लेने वाला पहला राष्ट्र बना। 1960 के दशक में कुछ अफ्रीकी देशों समेत अगले तीस वर्षों में बहुत अधिक राष्ट्र आईएमएफ में सम्मिलित हो गए। सोवियत ब्लॉक के राष्ट्र अपवाद बने रहे जो 1989 में बर्लिन की दीवार के पतन तक आईएमएफ का हिस्सा नहीं थे। आईएमएफ ने रूस के संस्था में सम्मेलन के साथ 1990 के दशक में सदस्यों में एक और बड़ी वृद्धि का अनुभव किया जिसमे रूस को आईएमएफ की कार्यकारी समिति में भी रखा गया था।

साहित्यावलोकन

ज्वोमो क्वामे सुन्दरम ने अपनी पुस्तक ''रिफ़ार्मिंग द इंटरनेशनल फाइनेंसियल सिस्टम फोर डिवलपमेंट'' में ब्रेटनवुड व्यवस्था के निर्माण एवं उसके डिजाईन की व्याख्या प्रस्तुत की है साथ ही पुस्तक के अंतर्गत लेखक ने व्यवस्थित डॉलर के वर्चस्व वाली प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के साथ–साथ इसके परिणामस्वरूप ब्रेटनवुड व्यवस्था के पतन का भी उल्लेख किया है। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उदय एवं के निर्माण, उद्देश्य एवं उनकी प्राप्ति में विसंगतियों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

पीटर बी केनन एवं अलेक्सजेंडर के स्वाबोदा ने अपनी पुस्तक रेफोर्मिंग द इंटरनेशनल मोनेटरी एंड फाइनेंसियल सिस्टम में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, उसकी मूलभूत कार्यप्रणाली की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करने के साथ–साथ परिवर्तित वैश्विक शक्ति संतुलन के अनुसार आये बदलावों की चर्चा प्रस्तुत की है । उक्त पुस्तक में लेखक ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एवं इंटरनेशनल मोनेटरी एंड फाइनेंसियल सिस्टम में सुधार हेतु व्यापक रूपरेखा भी प्रस्तुत की है ।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन आईएमएफ, विश्व बैंक एवं गैट ने प्रशंसनीय रूप से सतत् आर्थिक बाहली एवं विकास, पूर्ण रोजगार तथा आर्थिक कल्याण के साथ साथ आर्थिक क्षमताओं एवं सम्भावनाओं के पुर्ननिर्माण एवं विकास हेतु प्रोत्साहन दिया है। इन्होने संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न ऐजेन्सियों के साथ मिलकर जो कि अपने क्षेत्र में विशेषीकृत ऐजेन्सियां है, उन्नत आर्थिक विकास करने में सहयोग दिया है।[1]

1930 के दशक के दौरान उत्पन्न महामंदी के परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्थायें असफल हो गयी थी। स्वर्ण मानक की असफलता ने राष्ट्रों को व्यापार बाधाओं को बढ़ाने के, अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करने तथा निर्यात–दूसरे बाजारों में दूसरे राष्ट्रों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने और अपने नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन सभी कारकों ने कई देशों में विश्व व्यापार के पतन, उच्च बेरोजगारी और जीवन स्तर में गिरावट का नेतृत्व किया। वर्ष 1944 में ब्रेटनवुड्स समझौते ने एक नई अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक का निर्माण इसकी सबसे स्थायी विरासत में से थे। विश्व बैंक और आईएमएफ, जिन्हें अक्सर ब्रेटनवुड्स संस्थान कहा जाता है, दुनिया की आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था की संरचना का समर्थन करने वाले जुड़वां अंतर–सरकारी आधार–स्तंभ हैं। दोनों ने समयानुसार अपनी भूमिकाओं को विस्तारित किया है। विकास एवं मौद्रिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में दोनों संस्थाओं की अहम भागीदारी है। जिसमें इनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका में कुछ समानताओं के साथ कुछ असमानताऐं भी हैं।

ये दोनों पृथक–पृथक भूमिकाओं के साथ दो पृथक–पृथक संगठन हैं। इन और अन्य समानताओं के बावजूद विश्व बैंक और आईएमएफ पृथक रहते हैं। दोनों में मौलिक अंतर यह है कि बैंक मुख्य रूप से एक विकास संस्थान है जबकि आईएमएफ एक सहकारी संस्था है जो राष्ट्रों के मध्य भुगतान और प्राप्तियों की एक व्यवस्थित प्रणाली को बनाए रखता है। प्रत्येक का एक पृथक उद्देश्य है, एक पृथक संरचना है, ये विभिन्न स्रोतों से अपने वित्त पोषण प्राप्त करते हैं, विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों की सहायता करते है और विशिष्ट तरीकों के माध्यम से अपने पृथक–पृथक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते है।[2]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में असमानता

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक मौद्रिक प्रणाली का नियामक है जबकि विश्व बैंक एक वैश्विक वित्तीय संस्थान है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर बल देता है जबकि विश्व बैंक विकासशील राष्ट्रो में आर्थिक संवृद्धि पर बल देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एकपक्षीय संस्थान है जबकि विश्व बैंक एक बहुपक्षीय संरचना है

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान हेतु सदस्य राष्ट्रों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है जबकि विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों विशेषकर विकासशील राष्ट्रो को विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र एवं व्यष्टि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है जबकि विश्व बैंक का उद्देश्य गरीबी को कम करना तथा आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है।[3]

आईएमएफ के रूप में ब्रेटनवुड्स समझौते के रचनाकार जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्सटर व्हाइट ने एक ऐसी संस्था की कल्पना की थी जो अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, विनिमय दरों और अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों की देखरेख करेगी ताकि राष्ट्रों और उनके नागरिकों को एक–दूसरे से वस्तुएं और सेवाएं खरीदने में सक्षम बनाया जा सके।[4]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संरचना

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक के साथ जुड़वां संस्थानों में से एक है जिसे ब्रेटन वुड्स में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के मौद्रिक और वित्तीय प्रतिनिधिमंडलों के बीच चर्चा के परिणामस्वरूप 1944 को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के इतिहास में विशेष रूप से मौद्रिक क्षेत्र में एक महान ऐतिहासिक पहल थी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में राष्ट्र अपने निर्णयानुसार इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। संस्थान में वर्तमान में 189 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है।[5]

सदस्यों को उनकी अंश पूँजी के आधार पर संस्था में कोटा दिया जाता है जो संस्था की निर्णय–प्रक्रिया में उनके मताधिकार को सुनिश्चित करता है। कोटा का पच्चीस प्रतिशत या सदस्य देश के आधिकारिक स्वर्ण होल्डिंग्स का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, सोने में देय है– शेष कोटा सदस्य राष्ट्र की राष्ट्रीय मुद्रा के संदर्भ में भुगतान किया जाता है। हाल ही में,

सोने के भुगतान की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अंशदान में प्रत्येक राष्ट्र को एक निश्चित राशि मुद्रा कोष में जमा करनी पडती है। सदस्य देश को अपने कोटा का 25 प्रतिशत एसडीआर या कोष द्वारा चयनित किसी देश की मुद्रा में देना होता है। शेष राशि देश का अपनी मुद्रा में जमा करना होता है।[6]

वित्तीय सहायता के अतिरिक्त आईएमएफ प्रभावी नीतियों विशेष रूप से, आर्थिक, मौद्रिक और बैंकिंग नीति और विनियमों को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी सहायता भी सदस्य देशों को प्रदान करता है।

जनवरी 1970 से प्रभावी ड्रॉइंग राइट्स (एसडीआर) की एक प्रणाली स्थापित की गई थी। एसडीआर को सोने और आरक्षित मुद्राओं, जैसे पाउंड और डॉलर के पूरक के लिए डिज़ाइन किया गया है। एसडीआर पूरी तरह पेपर मनी का एक नया रूप प्रस्तुत करते हैं जो सोने या अमेरिकी डॉलर की तरह काम करेगा, और इसलिए इसे पेपर गोल्ड कहा जाता है।

विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Right - SDR)

विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) (Special Drawing Right) मूल रूप से एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक आरक्षित संपत्ति है। ट्रिफिन पैराडाक्स के जवाब में आईएमएफ द्वारा 1969 में एसडीआर बनाए गए थे। ट्रिफिन पैराडाक्स ने कहा था कि अधिक अमेरिकी डॉलर को आरक्षित रिजर्व मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है, अधिकतर राष्ट्रों को अमेरिकी सरकार की उन डॉलर को सोने में परिवर्तित करने की क्षमता पर कम भरोसा था। दुनिया अभी भी ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का उपयोग कर रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि एसडीआर अमेरिकी डॉलर को वैश्विक मौद्रिक आरक्षित मुद्रा के रूप में परिवर्तित कर देगा, इस प्रकार ट्रिफिन पैराडाक्स को हल किया जा सकेगा। वर्ष 1973 में ब्रेटनवुड्स व्यवस्था के पतन और विभिन्न मुद्राओं का चल (फ्लोटिंग) विनिमय दर व्यवस्था की ओर झुकाव ने वैश्विक रिजर्व परिसंपत्ति के रूप में एसडीआर पर निर्भरता कम कर दी। फिर भी, एसडीआर का आवंटन सदस्य देशों को तरलता प्रदान करने और आरक्षित भंडार को बनाने में एक भूमिका निभा सकता है। एसडीआर न तो मुद्रा है और न ही यह आईएमएफ पर दावा है। यह आईएमएफ सदस्यों की स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिए एसडीआर का आदान–प्रदान किया जा सकता है। प्रारंभ में एसडीआर को 0.888671 ग्राम सोने के बराबर परिभाषित किया गया था, जो उस समय एक अमेरिकी डॉलर के बराबर था। ब्रेटनवुड्स व्यवस्था के पतन के बाद एसडीआर मुद्राओं की टोकरी के रूप में फिर से परिभाषित किया गया। वर्ष 1978–80 में आईएमएफ एवं अमेरिकी सहयोग से समूह –5 के नीति निर्माताओं द्वारा विधि पूर्वक एक मैकेनिज्म पर वार्ता की गयी। इस प्रस्ताव के तहत विदेशी सरकारों द्वारा डॉलर को आईएमएफ के एक विशिष्ट ''स्थापन्न खाते'' में जमा कराने की अनुमति दी गयी तथा जो आईएमएफ की प्रमाणित मुद्रा एसडीआर में जमा हो जायेगें।[7]

एसडीआर का मूल्य

यू.एस. डॉलर के मामले में एसडीआर मूल्य प्रतिदिन दोपहर लंदन के समय स्पॉट एक्सचेंज दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और आईएमएफ वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है।

एसडीआर बास्केट की समीक्षा हर पांच वर्ष या उससे पहले की जाती है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि एसडीआर दुनिया के व्यापार और वित्तीय प्रणालियों में मुद्राओं के सापेक्ष महत्व को दर्शाता है। एसडीआर बास्केट की समीक्षा में एसडीआर के मूल्य निर्धारण के मुख्य तत्वों जिनमे प्रयुक्त मानदंड व संकेतक जो एसडीआर बास्केट की मुद्राओं का चयन करते है और एसडीआर बास्केट में प्रत्येक मुद्रा की मात्रा का निर्धारण करने में प्रयुक्त प्रारंभिक मुद्रा का भार से मूल्यांकन किया जाता है। बाजार विनिमय दरों के आधार पर एसडीआर का मूल्य दैनिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। नवंबर 2015 में समीक्षा के दौरान, बोर्ड ने फैसला किया कि चीनी रॅन्मिन्बी (आरएमबी) एसडीआर टोकरी में शामिल करने के मानदंडों को पूरा करता है। इस निर्णय के बाद 1 अक्टूबर 2016 से चीनी रॅन्मिन्बी (आरएमबी एसडीआर टोकरी में यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के साथ शामिल हो गया। वर्तमान में, आईएमएफ के पांच सबसे बड़े सदस्यों की मुद्राओं का मूल्य एक एसडीआर के मूल्य को निर्धारित करता है – अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन,यूरो और चीनी रॅन्मिन्बी, लेकिन इन मुद्राओं में भार समान नहीं होता है। एसडीआर अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में उद्धत किए गए हैं। बास्केट या मुद्राओं के समूह की समीक्षा आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड द्वारा हर पांच साल में की जाती है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में मुद्रा की भूमिका पर आधारित होती है।[8]

एसडीआर मुद्रा नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे आईएमएफ की मुद्रा के रूप में संदर्भित करते हैं। यह आईएमएफ पर दावा भी नहीं है, जो केवल एसडीआर खरीदने, बेचने और विनिमय करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। देशों को एसडीआर आवंटित किया जाता है, जो सदस्य देश के आरक्षित भंडार में शामिल होते हैं। मुद्राओं के साथ देशों के बीच एसडीआर का आदान–प्रदान किया जा सकता है। एसडीआर आईएमएफ और कुछ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है और देश आर्थिक आवश्यकताओं के समय एसडीआर में आईएमएफ से उधार लेता है।

मुद्रा का नाम	वर्ष 2015 में समिक्षा उपरान्त मुद्राओं का एस. डी.आर. में भार	1 अक्टूबर 2016 से प्रारम्भ पांच वर्षो की अवधि हेतु मुद्राओं की यूनिटस की एक निश्चित संख्या
अमेरिकी डॉलर	41.73	0.58252
यूरो	30.93	0.38671
चायनीज युआन	10.92	1.0174
जापानी येन	8.33	11.9
पोण्ड स्टर्लिंग	8.09	0.085946

एसडीआर ब्याज दर (The SDR Interest Rate- SDRI)

एसडीआर का मूल्य 5 आधार अंकों के साथ एसडीआर टोकरी में मुद्राओं के मनी मार्केट्स में अल्पावधि सरकारी ऋण उपकरणों पर प्रतिनिधि ब्याज दरों के भारित औसत के आधार पर साप्ताहिक रूप से निर्धारित किया जाता है। एसडीआरआई, सदस्यों द्वारा आईएमएफ से लिए गए गैर–रियायती उधार पर लगाए गए ब्याज दर की गणना करने और आईएमएफ में उनके पुनर्निर्मित लेनदार पदों के सदस्यों को भुगतान करने का आधार प्रदान करती है। एसडीआर होल्डिंग्स पर सदस्यों को ब्याज भी दिया जाता है और यह उनके एसडीआर आवंटन पर लगाया जाता है।

एसडीआर आवंटन और लेनदेन

समझौते के लेखों के तहत, यदि कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है तो आईएमएफ का एसडीआर विभाग उनके कोटा (सामान्य आवंटन के रूप में जाना जाता है) के अनुपात में एसडीआर आवंटित कर सकता है। एसडीआर तंत्र स्व–वित्त पोषित है और यह आवंटन पर शुल्क लेता है जिसका उपयोग एसडीआर होल्डिंग्स पर ब्याज का भुगतान करने के लिए किया जाता है। सदस्य स्वैच्छिक बाजार में एसडीआर खरीद और बेच सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो आईएमएफ सदस्यों को एसडीआर खरीदने के लिए भी नामित कर सकता है।[9]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संरचना एवं उद्देश्य/लक्ष्य

वर्तमान में 189 देश आईएमएफ के सदस्य हैं, उनमे से 24 देशों या देशों के समूह कार्यकारी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में आईएमएफ के प्रमुख उद्देश्य है।

1. आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना,
2. आर्थिक प्रगति को बढावा देना,
3. वैश्विक रोजगार को बढावा देना तथा गरीबी को कम करना,
4. अन्तर्राष्ट्रीय विकास में वृद्धि करना तथा पारस्परिक सहयोग को बढावा देकर उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना,
5. राष्ट्रो के मध्य विनिमय व्यवस्था को सुदृढ बनाना तथा प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन को बचाना,
6. मुद्रा सम्बन्धी नीतियो पर विश्व जनमत में अनुकूलतम नीति पर एक राय कायम करना,
7. भुगतान असंतुलन की स्थिति से सुरक्षित रखना,
8. आर्थिक रूप से संकटग्रस्त राष्ट्रो को मुद्रा कोष से संसाधन उपलब्ध कराना,
9. विभिन्न राष्ट्रो के मध्य चालू लेन देन को सुलभ बनाना तथा विदेशी विनिमय को बढावा देना।[10]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में निरन्तर योगदान कर रहा है। जिससे उसकी भूमिका अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सम्बन्धों में निरन्तर विस्तारित हो रही है। मुद्रा कोष की भूमिका का विवेचन निम्न प्रकार किया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए और रोजगार तथा वास्तविक आय के उच्च स्तर को प्राप्त करना और आर्थिक नीति के प्राथमिक उद्देश्यों के रूप में सभी सदस्यों के उत्पादक संसाधनों के विकास के लिए योगदान देना इसके मुख्य उद्देष्य है। विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों के बीच व्यवस्थित विनिमय व्यवस्था बनाए रखना और सदस्यों के मध्य प्रतिस्पर्धी विनिमय मूल्यह्रास को कम करना तथा सदस्यों के बीच मौजूदा लेनदेन और विदेशी मुद्रा प्रतिबंधों को खत्म करने जो विश्व व्यापार के विकास में बाधक हैं,के लिए भुगतान की बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करना भी इसके लक्ष्यों में सम्मिलित है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य

1. **विनिमय दर को विनियमित करना** – संस्था में सम्मिलित होने पर प्रत्येक सदस्य–देश को सोने या अमेरिकी डॉलर के मामले में अपनी मुद्रा के बराबर मूल्य घोषित करता है (अब एसडीआर के मामले में) जो इस समानता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हालांकि, यह आईएमएफ की अनुमति के बिना इसे 10 प्रतिशत तक बदल सकता है। 10 प्रतिशत तक और बदलाव के लिए आईएमएफ से परामर्श लेना परामर्ष लेना होता है। जिसके लिए प्रस्तावित परिवर्तन को 72 घंटे के भीतर स्वीकृति या अस्वीकृत करना होता है। आईएमएफ की सहमति के साथ ही भुगतान संतुलन में "मौलिक असमानता" को सही करने के लिए 20 प्रतिशत से अधिक परिवर्तनों को प्रभावित किया जा सकता।
2. **भुगतान संतुलन की समस्या का निपटान–** जब कोई देश चालू खाते पर भुगतान की शेष राशि में घाटे से पीड़ित होता है, तो वह अपनी मुद्रा के बदले आईएमएफ से ऋण के रूप में उस मुद्रा को प्राप्त कर सकता है, जिस मुद्रा में राष्ट्र को घाटे का भुगतान करना होता है।
3. **दुर्लभ मुद्राओं का मूल्यांकन करना–** सदस्य देशों और आईएमएफ द्वारा बड़े रूप में मांग में आने वाली मुद्राएं जिन्हें दुर्लभ मुद्राओं के रूप में घोषित किया जाता है और उन्हें उन देशों के बीच आईएमएफ द्वारा विनियमित किया जाता है। आईएमएफ उधार लेने या सोने के विरुद्ध उन्हें खरीदकर ऐसी 'दुर्लभ' मुद्राओं की आपूर्ति में भी वृद्धि कर सकता है। सदस्य देशों को ऐसी 'दुर्लभ' मुद्राओं के नकदी में विनिमय प्रतिबंध लगाने की अनुमति है।
4. **विनिमय प्रतिबंधों का उन्मूलन–** आईएमएफ को यह देखना होता है कि सदस्य–देश वर्तमान लेनदेन पर विनिमय प्रतिबंध लागू नहीं करते हैं। युद्ध के बाद मौजूद असामान्य स्थितियों को देखते हुए आईएमएफ ने 3 साल से अधिक समय तक संक्रमण की अवधि की अनुमति दी जिसके दौरान सदस्य ऐसे प्रतिबंध लागू कर सकते थे। अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात कई देशों ने अपने विनिमय प्रतिबंधों को कम कर दिया है। हालांकि, निकट भविष्य में उनका पूरा निष्कासन संभव नहीं है। आईएमएफ ऐसे विनिमय प्रतिबन्धों का उन्मूलन करता है।[11]

अपनी स्थापना से ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सरकारों को आधारभूत असंतुलन की स्थिति में अपनी मुद्रा के मूल्य को समायोजन करने की अनुमति प्रदान की है।

दूसरा, आईएमएफ ने राष्ट्रो को उनकी तत्कालीन भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान करने के लिये अल्प कालीन ऋण उपलब्ध करा उनकी वित्तीय स्थिति को स्थिरता प्रदान की है। आईएमएफ ने वैश्विक मौद्रिक एवं वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्र–राज्यों की सरकारों को व्यापक भूमिका प्रदान की है। आईएमएफ के अधिदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि इसने वृहत् अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक असंतुलन के सदर्भ में राष्ट्रो को अपनी नीति निर्माण प्रक्रिया में बदलाव हेतु प्रेरित किया है।[12]

सामान्यतः आईएमएफ अपने परम्परागत दृष्टिकोण के तहत सदस्य देशों को संकट के समय सशर्त सहयोग प्रदान करता है जो कि हाल ही के समय में आईएमएफ की भूमिका को लेकर उसके सहायता पैकेज एवं शर्तो के मध्य एक विरोधाभासी दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ है। जिसमें जटिलता यह है कि आईएमएफ द्वारा संकट के समय दिया गया सहायता पैकेज तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। जबकि उससे सम्बन्धित शर्ते भारी होती है। जो राष्ट्र–राज्यों के आन्तरिक मामलो को प्रभावित करती है। कुछ समकालीन राहत पैकेजो के संदर्भ में केवल आईएमएफ ही पैकेज उपलब्ध नही कराता अपितु विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, अन्तर अमरीकी विकास बैंक तथा द्विपक्षीय रूप से सरकारो एवं केन्द्रीय बैंको द्वारा भी अतिरिक्त रूप से सहायता उपलब्ध करायी जाती है।[13]

आईएमएफ अन्यों के सहयोग से एक साथ कई मोर्चो पर कार्य करता है। इसमें संस्थान की गहन निगरानी प्रक्रिया के माध्यम से नीतिगत सलाह का प्रावधान है जो विशेषज्ञ सलाह के माध्यम से तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण के व्यापक कार्यक्रम द्वारा कौशल विकसित करने में सहायता करता है तथा योग्य सदस्यों को वृहत् संरचनात्मक समायोजन सुविधा (जो अब गरीबी उन्मूलन एवं विकास सुविधा के नाम से जानी जाती है) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आईएमएफ मुख्यतः विश्व के सबसे गरीब एवं भारी ऋणग्रस्त गरीब राष्ट्रो को ऋण सहायता उपलब्ध करा उनकी अर्थव्यवस्थाओं को सम्बल प्रदान करता है।[14]

उल्लेखनीय है 90 के दशक में पूर्वी एषियाई आर्थिक संकट के समय आईएमएफ ने पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की भारी मदद की। उसका तुरन्त लक्ष्य था प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में विश्वास पैदा करना। इसके लिए दक्षिण कोरिया, थाईलैण्ड, और इण्डोनिया में आईएमएफ ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु करने की व्यवस्था की। आईएमएफ ने आर्थिक सुधारों के लिए इन तीन देशों को 36 अरब डॉलर का वित्तीय समर्थन दिया और 82 अरब डॉलर दूसरो स्रोतों से दिलवाने में सहायता प्रदान की।[15] साथ ही 20 वीं शताब्दी के सबसे भयावह आर्थिक संकटो यथा अमेरीकी सब–प्राईम संकट तथा यूरोपीयन संकट के समय आईएमएफ ने प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने में महती भूमिका अदा की।

आईएमएफ की कार्यप्रणाली एवं अग्रणी तंत्र

आईएमएफ अपने सदस्य देशों को कई प्रकार से उनके अलग–अलग कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करता है। जिसके तहत संस्था वैश्विक वित्तीय प्रणाली के सुदृढीकरण एवं स्थिरता हेतु अपने प्रयासों को निम्न कार्यक्रमो के माध्यम से गतिशील बनाये रखता है –

1. **स्टैंड–** इन व्यवस्थाएः आईएमएफ द्वारा उधार देने का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला तरीका स्टैंड–इन व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत एक क्रेडिट किश्त जो सदस्य देश के कोटा के 100 प्रतिशत के बराबर है, उसे उधार देने के लिए उपलब्ध होती है। एक सदस्य देश भुगतान की कठिनाइयों को पूरा करने के लिए इस क्रेडिट किश्त से आईएमएफ से उधार ले सकता है। सरकारी व्यय और धन आपूर्ति लक्ष्यों के संबंध में एक निश्चित मानदंड संसाधनों को जारी करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए, खासकर उच्च क्रेडिट शाखाओं में। यह उम्मीद की जाती है कि इस व्यवस्था के तहत उधार लेने वाले देश की सरकार भुगतान संतुलन के स्तर को सुधारने के उपायों को अपनाएगी। आम तौर पर, स्टैंड–बाय व्यवस्था 12–18 महीने की अवधि के लिए होती है। इस व्यवस्था के तहत ऋण की चुकौती आईएमएफ को प्रत्येक ड्राइंग के 3–5 साल के भीतर की जाती है।
2. **विस्तारित फंड सुविधा (Enhance Fund Facility - EFF):** विस्तारित फंड सुविधा 1974 में विकसित देशों की तुलना में विकासशील देषो को लम्बी अवधि (3 साल तक) हेतु सहायता के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा, इस सुविधा में विकासशील देश अपने कोटा से अधिक उधार ले सकते हैं। इस सुविधा के तहत लिए गए ऋणों को 4–10 साल की अवधि में वापस भुगतान किया जा सकता है। विस्तारित निधि सुविधा के तहत, चूंकि विकासशील देश लंबी अवधि के भुगतान की कठिनाइयों के लिए उधार ले सकते हैं क्योंकि इस योजना के तहत उधार सुविधा का लाभ उठाने के लिए कड़ी शर्तों को पूरा किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत उधार लेने वाले देश को हर साल भुगतान की समस्याओं के संतुलन को हल करने के लिए अपनाए गए उपायों और नीतियों का एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करनी होती है। आईएमएफ से उधार लेने वाले देश द्वारा किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में सशर्तता के साथ किश्तें जारी करता है "स्टैंड–बाय व्यवस्था और विस्तारित फंड सुविधा (ईएफआई) आईएमएफ द्वारा विकासशील देशों की भुगतान कठिनाइयों के संतुलन को पूरा करने के लिए वित्त सहायता के बहुत महत्वपूर्ण तरीके हैं।

   हालांकि हाल के वर्षों में आईएमएफ द्वारा प्रदान की गई अन्य विशेष सुविधाओं का विकास विकासशील देशों द्वारा बड़े पैमाने पर भुगतान संतुलन से उत्पन्न होने वाली समस्या से निपटने के लिए किया जा रहा है। जिनमे से महत्वपूर्ण विशेष सुविधाएं हैं
3. **गरीबी में कमी और विकास सुविधा (Poverty Reduction and Growth Facility - PGRF):** यह फण्ड वर्ष 1999 में गरीबी में कमी के लिए कम आय वाले देशों अर्थात विकासशील देशों को वित्तीय

सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। इससे पहले, आईएमएफ ने गरीब विकासशील देशों को उन्नत संरचनात्मक समायोजन सुविधा के नाम से जाना जाने वाला कार्यक्रम के तहत वित्त प्रदान किया ताकि वे संरचनात्मक समायोजन सुधार कर सकें। 1999 में विकासशील देशों में गरीबी में कमी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसलिए 1999 में उन्नत संरचनात्मक समायोजन सुविधा को गरीबी न्यूनीकरण और विकास सुविधा (पीआरजीएफ) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। विश्व बैंक और अन्य विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार गरीबी न्यूनीकरण रणनीति पेपर के आधार पर इस कार्यक्रम के तहत गरीब देशों को आईएमएफ द्वारा सहायता प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम के तहत आईएमएफ द्वारा दिए गए ऋणों पर न्यून ब्याज जो प्रति वर्ष 0.5 प्रतिशत है, आरोपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऋणी राष्ट्र इस कार्यक्रम के तहत 10 वर्षों की लंबी अवधि में दिए गए ऋण चुका सकता है।

4. **पूरक रिजर्व सुविधा (Supplemental Reserve Facility - SRF):** यह सुविधा वर्ष 1997 में पूर्वी एशिया और अन्य विकासशील देशों में आए वित्तीय संकट के प्रत्युत्तर में स्थापित की गयी थी । इस सुविधा के तहत, आईएमएफ उन सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो बाजारों में आकस्मिक संकट से उत्पन्न असंतुलन से अपनी मुद्राओं में भुगतान संतुलन की समस्या का अनुभव करते हैं। एसआरएफ के तहत दी जाने वाली सहायता सामान्य कोटा सीमाओं के अधीन नहीं है बल्कि इसके बजाय देश की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। ऋण और नीतियों को पुनर्भुगतान करने की इसकी क्षमता को आत्मविश्वास बहाल करने के लिए इसे अपनाया जाता है। जिसमे ऋण लेने के 2.5 साल के भीतर चुकौती की जानी चाहिए।

5. **आकस्मिक क्रेडिट लाइन (Contingent Credit Line - CCL):** यह सुविधा देशों की उन समस्याओं से निपटने के लिए वर्ष 1999 में स्थापित की गई थी जो वित्तीय संकट का अनुभव कर रहे हैं तथा ऐसी स्थिति जिसमे भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाते पर पूंजीगत बहिर्वाह का संकट भविष्यामि हो। पूंजीगत खाते पर आने वाले संकटों को दूर करने के लिए देश को सहायता प्रदान करने के लिए यह एक सावधानी पूर्वक अपनाया गया उपाय था। इस सुविधा के तहत लिए गए ऋण के लिए चुकौती अवधि भी 2.5 वर्ष होती है।

6. **विशेष तेल सुविधा (Special Oil Facility - SOF):** वर्ष 1973 के अरब तेल तेल संकट ने विकसित और विकासशील देशों के लिए भुगतान संतुलन की समस्या को सबसे गंभीर बनाया। विकासशील देशों में भारत सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। सदस्य देशों की सहायता के लिए आईएमएफ ने एक विशेष निधि शुरू की है, जिससे गंभीर कठिनाइयों में सदस्य देशों की मदद की जाती है। इसे विशेष तेल सुविधा कहा जाता है।[16]

भारत एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक राष्ट्रों में रहा है जो प्रारंभ से ही एक स्थिर एवं समृद्धिकारी विश्व के निर्माण का समर्थक रहा है। भारत आईएमएफ का संस्थापक राष्ट्र है। वर्ष 1992 तक भारत द्वारा आईएमएफ से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नही ली गयी थी। वर्ष 1992 में भारत द्वारा किये गये आर्थिक सुधारो के लिये आईएमएफ ने भारत की वित्तीय सहायता की। वर्ष 2000 तक भारत ने आईएमएफ के समस्त ऋण चुकता कर दिये थे।[17] मुद्रा कोष की सदस्यता से भारत को अनेक क्षेत्रों में आवश्यक लाभ प्राप्त हुये है। जिसमे मुद्रा के क्षेत्र में आईएमएफ द्वारा किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विनियमन ने निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और इस प्रकार समृद्धि के विस्तार में योगदान दिया है। मुद्रा कोष की उपयोगी नीतियों एवं कार्यक्रमों से भारत बहुत हद तक लाभान्वित हुआ है। भारत को मुद्रा कोष द्वारा न केवल बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई हैं अपितु प्रत्यक्ष रूप से उसकी सदस्यता का भारत को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। विभाजन के बाद की अवधि में, भारत में भुगतान संतुलन के घाटे का गंभीर संकट था, विशेषकर, डॉलर और अन्य हार्ड मुद्रा वाले राष्ट्रों के साथ। उस स्थिति में भारत संभवत अपने आयात कम नहीं कर सका, क्योंकि इनमें आवश्यक खाद्य पदार्थ, पूंजीगत उपकरण और औद्योगिक कच्चे माल शामिल थे। दूसरी तरफ, उसके निर्यात को देश में सीमित उत्पादन की शर्तों के तहत तुरंत विस्तार नहीं किया जा सका, निर्यात में वृद्धि गंभीर आंतरिक कमी पैदा करने के लिए काफी थी। इस तरह की कठिन परिस्थिति में, यह आईएमएफ ही था जो उसके बचाव में आया।

आईएमएफ से भारत द्वारा उधार के कुल आंकड़े उस समर्थन की सीमा को व्यक्त नहीं करते हैं जिससे इसे बढ़ाया गया है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मुद्रा कोष द्वारा भारत को दी गयी सहायता तब दी गयी थी जब देश को गंभीर विदेशी मुद्रा स्थितियों का सामना करना पड़ा था।

आईएमएफ की सदस्यता ने भारत को एक और महत्वपूर्ण तरीके से लाभान्वित किया है। भारत अपनी विभिन्न नदी परियोजनाओं, भूमि पुनर्वास योजनाओं और संचार विकास के लिए बड़ी विदेशी पूंजी चाहता था। चूंकि निजी विदेशी पूंजी प्राप्त करना आसन नहीं था, इसलिए आवश्यक पूंजी प्राप्त करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका विकास और पुनर्निर्माण के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (यानी विश्व बैंक) से उधार लेना था। आईएमएफ की सदस्यता विश्व बैंक की सदस्यता के लिए एक आवश्यक शर्त है। इस प्रकार, आईएमएफ की भारत की सदस्यता ने उसे विश्व बैंक और उसके सहयोगियों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) के सदस्य होने का हकदार बनाया है। वास्तविकता में, पूर्ण आंकड़ों में हालांकि प्रति व्यक्ति आधार पर नहीं, भारत विश्व बैंक समूह का सबसे बड़ा उधारकर्ता रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी–

International Financial Corporation) ने उर्वरकों, कास्टिक सोडा, गोंद और बीयरिंग, पंप इत्यादि के उत्पादन में लगी भारतीय कंपनियों में पर्याप्त निवेश किया है। विश्व बैंक से भारत द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता का एक बड़ा हिस्सा सॉफ्ट–लोन एफिलिएट से है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए–International Development Agency) द्वारा दिया गया ऋण 50 साल से अधिक की अवधी में देय है जो ब्याज मुक्त है तथा प्रति वर्ष मात्र 0.75 प्रतिशत की एक सेवा शुल्क उस पर वसूल की जाती है। वित्तीय वर्ष 1975–76 (जुलाई–जून) के बाद से, विश्व बैंक 375 डॉलर से कम की प्रति व्यक्ति आय वाले देशों की सहायता के लिए "तीसरी विंडो" ऋण का विस्तार कर रहा है। भारत को 'तीसरी विंडो' से काफी मात्रा में निधि प्राप्त हुई है।

भारत ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से आईएमएफ के विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया है। विशेषज्ञों की टीम अक्सर भारत आती हैं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट जमा करती है। इस तरह भारत को मुद्रा कोष की स्वतंत्र जांच और सलाह का लाभ मिल रहा है।

विश्व व्यापार और वित्त के क्षेत्र में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय परिषदों में इस तरह के महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया है जो निर्णय–प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मुद्रा कोष अपनी नीतियों द्वारा सदस्य राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक सामंजस्य या मैत्री (concord) को स्थापित करने में महत्ती भूमिका का निर्वाह करता आ रहा है। अपनी सदस्यता के अनुसार, अपने स्वयं के लाभ के अलावा, वह मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग में निरंतर योगदान दे रहा है।

अक्टूबर 1973 से तेल की कीमत में वृद्धि के कारण भारत की भुगतान स्थिति का संतुलन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया था, आईएमएफ ने इस स्थिति से निपटने के उद्देश्य से एक विशेष निधि स्थापित करके भारत को तेल सुविधा उपलब्ध कराई थी। आईएमएफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत दुनिया के विकासशील देशों में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राष्ट्र था। इसलिए आईएमएफ से यह विशेष सहायता उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अक्टूबर 1974 में, भारत ने आईएमएफ से 194 करोड़ और अगस्त 1975 में 207 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त की थी। वर्ष 1981 में भी भारत 5000 करोड़ रुपये की भुगतान के संतुलन की समस्या को सुलझाने के लिए मुद्रा कोष से बड़े पैमाने पर ऋण प्राप्त करने में सफल रहा था। यह एक सदस्य देश को आईएमएफ द्वारा किया गया सबसे बड़ा ऋण था। भारत ने विवेकशील रूप से इस ऋण का इस्तेमाल किया और शेष राशि आईएमएफ को समर्पण कर दी।

ग्रीस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल जैसे कई यूरोपीय देशों की ऋण जमानत देने के लिए मुद्रा कोष पर ध्यान केन्द्रित किया गया था जो गंभीर संप्रभु ऋण संकट का सामना कर रहे थे। उस समय आईएमएफ के अपने ऋण फंड में 384 बिलियन की राशि थी जो यूरोपीय देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी अपर्याप्त एवं सीमित थी। साथ ही, अमेरिका, जर्मनी जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में तत्कालीन आर्थिक और राजनीतिक वातावरण में यह असंभव था कि वे आईएमएफ को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवा सके। आईएमएफ को अक्टूबर 2011 में अपनी स्टीयरिंग कमेटी द्वारा इसकी समीक्षा करने के लिए पूछा गया था कि क्या इसके संसाधन पर्याप्त हैं। आईएमएफ के अध्यक्ष क्रिस्टीन लोगार्ड के अनुसार, धन की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता सबसे खराब परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी अनुमानित क्षमता पर निर्भर करती है। उन्होंने आगे कहा कि संभावित वित्त पोषण आवश्यकताओं और ऋण से भरे यूरोपीय देशों में संकट की तुलना में उधार क्षमता आज आरामदायक लगती है। ऐसी स्थिति में भारत द्वारा अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता का परिचय देते हुये आईएमएफ से 200 टन स्वर्ण की खरीद इसलिए की ताकि आईएमएफ की फण्ड की जरूरत पूरी हो सके। जिससे वह यूरोपीयन राष्ट्रो को ऋण उपलब्ध करवा पाये।[18]

अध्ययन का उद्देश्य

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कार्यप्रणाली को समझना है। साथ ही अध्ययन का उद्देश्य समकालीन वित्तीय व्यवस्था में आ रहे परिवर्तनों के अनुरूप मुद्रा कोष की भूमिका की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करना है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में संरचनात्मक एवं प्रचालनीय सुधार हेतु प्रयास की व्याख्या की गयी है साथ ही अध्ययन का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारत के विकास के साथ सम्बन्ध को समझना है।

निष्कर्ष

समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पूर्णतयाः राष्ट्रीय हितों से प्रेरित हो मुक्त व्यापार की दिषा का अनुगमन कर रही है। मुक्त व्यापार की ऐसी परिस्थितियों ने समय – समय पर विश्व व्यापार में तनाव एवं जीवन स्तर को कमजोर भी किया है। अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक विकास एवं भारत के विकास में महती योगदान दिया है। किन्तु परिवर्तित नवीन वैश्विक शक्ति संतुलन के अनुसार कोष की भूमिका में बदलाव आये हैं । कहीं कहीं पर अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष कमजोर हुआ है जिसके लिए समय समय पर इसमें सुधार की मांग उठती रही हैं ।

अंत टिप्पणी

1. *सुन्दरम, ज्वोमो क्वामे, रिफ़ार्मिंग द इंटरनेशनल फाइनेंसियल सिस्टम फोर डिवलपमेंट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयार्क, 2011,पृ. 5*
2. *वही सुन्दरम, ज्वोमो क्वामें, पृ. 13*
3. *ड्रिस्कोल, डी डेविड, आईएमएफ और विश्व बैंक : कैसे वे भिन्न हैं, एक्सटरनल रिलेशन्स डिपार्टमेंट पब्लिकेशन सर्विसेज इंटरनेशनल मोनेटरी फंड वाशिंगटन डीसी 20431 यू.एस.ए., अगस्त 1996*
4. *सिन्हा, सच्चिदानन्द, भूमण्डलीकरण की चुनौतियां, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2006, पृ. 26*
5. *मुखर, सुबो, रोल ऑफ इंटरनेशनल मोनेटरिंग फंड इन इंडिया , इकोनोमिकडिसक्सन डॉट नेट*
6. *बलाम, डेविड एन और बेसेथ माईकल, इन्ट्रोडेक्शन टू इंटरनेशनल पोलेटिकल ईकोनोमी, ब्रंट, फिलिपा, वाई ऑस्ट्रेलिया शुड ज्वाईन द एशियन इन्फ्रास्ट्रेक्चर इनवेस्टमेंट बैंक, द इंटरप्रेटर, लोवी इंस्टीट्यूट फोर इंटरनेंशनल पॉलिसी*
7. *चतुर्थ संस्करण, एनजेपीयर्ससन एजूकेशन इंटरनेशनल प्रेन्टिस हॉल सा विनोद कुमार, वैश्विक*

राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, डिस्कवरी पब्लिशिंग हॉल 2005

8. *सुन्दरम, ज्वोमो क्वामे, रिफ़ार्मिंग द इंटरनेशनल फाइनेंसियल सिस्टम फोर डिवलपमेंट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस न्यूयार्क, 2011,पृ. 13 और 121*
9. *स्पेशल ड्रोइंग राईट्स इंटरनेशनल मोनेटरी फंड , आईएमएफ डॉट ओआरजी*
10. *वही आईएमएफ डॉट ओआरजी*
11. *त्रिपाठी श्रीप्रकाश मणि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, प्रत्यूश पब्लिकेशनस दिल्ली पृ. 240*
12. *मुखर, सुबो, रोल ऑफ इंटरनेशनल मोनेटरिंग फंड इन इंडिया , इकोनोमिकडिसक्सन डॉट नेट*
13. *केनन,बी पीटर, स्वाबोदा, के एलेक्जेंडर, रिफार्मिंग द इंटरनेशनल मोनेटरी एंड फाइनेंसियल सिस्टम इंटरनेशनल, मोनेटरी फंड पब्लिकेशन सर्विसेस वाशिंगटन डी.सी,पृ. 13*
14. *वही , केनन,बी पीटर,स्वाबोदा,के एलेक्जेंडर पृ. 15*
15. *द ईकोनोमिस्ट एक्सप्लेन, द ईकोनोमिस्ट 11नवंबर 2014*
16. *मुखर, सुबो, रोल ऑफ इंटरनेशनल मोनेटरिंग फंड इन इंडिया , इकोनोमिकडिसक्सन डॉट नेट*
17. *धर्मेन्द्र कुमार सिंह, चौथी दुनिया, 3 जुलाई, 2016*
18. *मैक्लिनसी, स्टीफन, वाल्टर्स रोजी और शीनफ्लग क्रिस्टीन, इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, ई– इंटरनेशनल रिलेशंस पब्लिशिंग , ब्रिस्टल, लंदन, पृ. 74*